व्यापार संगठनों ने राजस्थान सरकार से निविश नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में व्यापार निकायों ने राज्य को निविशक-अनुकूल बनाने के लियै **राजस्थान निविश प्रोत्साहन योजना (RIPS) और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)** जैसी नीतियों को बदलने का अनुरोध किया।

मुख्य बिंदु:

- RIPS नीति में निविशकों को **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)**, विद्युत शुल्क, भूमि कर, स्टांप शुल्क आदि पर सब्सिडी मिलती है।
- MLUPY योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और रोज़गार सृजन के लिये रियायती बैंक ऋण प्रदान करती है।
- **एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)** के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य से मुलाकात की।
    - इसमें बताया गया है कि RIPS के तहत **ब्याज लाभ सावधि ऋण पर उपलब्ध थे, लेकिन कार्यशील पूंजी ऋण पर नहीं।**
    - प्रतिनिधिमंडल ने योजनाओं के बारे में **उद्योग-व्यापी जागरूकता कार्यक्रम** चलाने का अनुरोध किया।
    - इसने यह भी अनुरोध किया कि **भंडारण क्षेत्र को उद्योगों के पूर्वावलोकन के तहत कवर किया जाए।**

राजस्थान निविश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

- राज्य में तीव्र, सतत् एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये **17 दिसंबर, 2019** से 'राजस्थान निविश प्रोत्साहन योजना-2019' लागू की गई।
- इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नए निविश के लिये **7 वर्ष के SGST**, विद्युत कर स्टाम्प ड्यूटी का **75% रिचार्ज** भी किया जा रहा है।
    - इसके साथ ही मंडी शुल्क में 100 फीसदी जैसी रियायतें भी दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

- यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के **सभी वर्गों को रोज़गार सृजन के नए अवसर प्रदान करने के लिये वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने** के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- योजना के तहत वित्तीय संस्थानों जैसे (**राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,** अनुसूचित लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, **राजस्थान वित्तीय निगम, सिडबी एवं** शहरी सहकारी बैंक) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिये ऋण प्रदान किया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/trade-bodies-urge-rajasthan-government-to-make-changes-in-investment-policies